



क्रमांक/मा.चि./2023/813
प्रति,

छतरपुर, दिनांक 01/06/23

विषय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कक्ष भू-प्रबंध)
सतपुड़ा भवन भोपाल
छतरपुर जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 'एक्सटेंशन गुलमंज-अमानमंज-पवाई-कटनी मार्ग के चौड़ीकरण/निर्माण हेतु 30.428 हेक्टेयर वनभूमि म0 प्र0 सड़क विकास निगम, सागर को उपयोग पर देने बाबत।
संदर्भ :- आपका पृष्ठांकन क्रमांक/एफ-5/885/2019/10-11/1786 दिनांक 29.05.2019
—00—

विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से चाही गई 03 बिन्दुओं पर जानकारी तैयारकर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है :-

1. वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर का प्रमाण-पत्र अपलोड कर हार्डकॉपी संलग्न है।
2. वनमंडल छतरपुर द्वारा पूर्व में सम्प्रेषित प्रस्ताव अंतर्गत आवेदित व्यपवर्तन हेतु 30.428 हेक्टेयर क्षेत्र में से परिक्षेत्र बड़ामलहरा अंतर्गत आने वाले 2.030 हेक्टेयर वनभूमि, RF-71 से गुजरने वाले मार्ग का उल्लेख त्रुटिवश नहीं किया गया था। जिसका सत्यापन वन परिक्षेत्राधिकारी बड़ामलहरा द्वारा करवाया गया है (प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न)।
3. आवेदक संस्थान द्वारा बिन्दु क्रमांक 03 के संबंध में भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06 जुलाई 2020 को जारी मिनट्स की कॉपी संलग्न कर केन्द्र सरकार के अधीन आने वाले विभागों को वैकल्पिक वृक्षारोपण में राजस्व भूमि उपलब्ध करवाने हेतु मुक्त रखते हुए दुगने बिगड़े वन पर वृक्षारोपण कार्य करवाने हेतु सहमति दी गई है (छायाप्रति संलग्न)।

उपरोक्तानुसार बिन्दुवार जानकारी संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(वेणी प्रसाद दत्तानिया)
वन मण्डलाधिकारी

सा. वन मण्डल छतरपुर

पृष्ठां. क्रमांक/मा.चि./2023/814

छतरपुर, दिनांक 01/06/23

प्रतिलिपि :- 1. मुख्य वन संरक्षक, वृत्त छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. संभागीय प्रबंधक, म0 प्र0 सड़क विकास निगम सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(वेणी प्रसाद दत्तानिया)
वन मण्डलाधिकारी
सा. वन मण्डल छतरपुर

FORM -I
(For projects linear projects)

Government of M.P.

Office of the District Collector, Chhatarpur

No.FRA/Tribal/2022-23 10683

Chhatarpur Date 26/10/22

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted For Non Forest purpose read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that total area 30.426 hec. Hectares in Compartment No P-71,321,322,323,347,370,3-69,374,368,371,373,428,429,427,432 Forest Land and in favour of MPPWD Sagar (MP) for a part of Gulganj-Amanganj-Pawai-Katni Road NH-43 Ext.Details are given below.

It is further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 30.426 in Compartment No P-71,321,322,323,347,370,3-69,374,368,371,373,428,429,427,432 of forest land A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure —to— Annexure.
- (b) The diversion of forest land and Revenue forest for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl: As above


Collector
Distt. Chhatarpur

कार्यालय कलेक्टर, (जन जातीय कार्य विभाग) जिला छतरपुर म.प्र.

क्र./वन अधिकार/2022-23/10688

प्रति,

छतरपुर दिनांक 26/10/22

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग(रा.रा.)
सागर संभाग सागर

विषय :-

संदर्भ :-

वन अधिकार अधिनियम 2006 अंतर्गत प्रपत्र-1 प्रदाय करने बावत।

आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक /366/कार्य/2020-21/सागर दिनांक 01.02.2021 प्राप्ति दिनांक 30.07.2021

—00—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग 43 (विस्तार) गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के खण्ड किमी. 0+00 से किमी. 43+00 तक (ग्राम गुलगंज से बराना नदी, ग्राम कुपी) चौड़ीकरण एवं एकरेखड़ सुधार कार्य में वन मण्डल छतरपुर के वन परिक्षेत्र बिजावर के क्षेत्रांतर्गत वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत विनिश्चय प्रमाण-पत्र चाहा गया है, उक्त के संबंध में अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर को सम्पूर्ण प्रकरण भेजा जाकर प्रस्ताव में वन अधिकार समिति, ग्राम सभा, एवं उपखण्ड स्तरीय समिति से नियमानुसार प्रस्ताव चाहा गया था जो कि उनके पत्र क्रमांक/964/वन.मा.अधि./वनाधिकार/2022 दिनांक 29.07.2022 प्राप्त हो चुका है।

उपखण्ड स्तरीय समिति का प्रस्ताव प्रमाण-पत्र, पत्र दिनांक 04.05.2022 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति का ठहराव (विनिश्चय) दिनांक 11.01.2022, ग्राम सभा का कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 11.01.2022, के आधार पर वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग(रा.रा.) सागर संभाग सागर के सन्दर्भित आवेदन पर ग्राम सभा पहाड़ी बावन के ग्राम सपौहां तहसील राजनगर के कम्पार्टमेंट कक्ष क्रमांक पी-00683 रकबा 8.212 हे० के विनिश्चय प्रमाण-पत्र देने के संबंध में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त कक्ष क्रमांक के आस-पास स्थित ग्रामों में रहने वाले स्थानीय ग्रामीण परिवारों को जंगल से प्राप्त होने वाली आय अकास्तीय लघु वनोपज (N.T.F.P.) एवं अन्य तैदूपत्ता संग्रहण जो कि कम्पनी द्वारा एवं म०प्र० शासन तथा भारत शासन के वर्तमान एवं इस संबंध में भविष्य के निर्णय के अनुसार एवं मुआवजा/कार्यवाही विधि अनुसार संपादित की जावेगी।

अतः पत्र के साथ संलग्न प्रमाणित कार्यवाही विवरण उपखण्ड स्तरीय समिति का प्रस्ताव प्रमाण-पत्र दिनांक 04.05.2022, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति का ठहराव (विनिश्चय) दिनांक 11.01.2022, ग्राम सभा का कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 11.01.2022, के आधार पर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में लिये गये निर्णय के अनुसार ही विनिश्चय प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है।

उपरोक्त संलग्न निर्णयों के अनुसार ही कार्यवाही सम्पादित की जाना अनिवार्य होगा। पत्र के साथ विनिश्चय प्रमाण पत्र तथा अन्य सहपत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।
संलग्न - उपरोक्तानुसार।

जिला संयोजक

जनजातीय कार्य विभाग

छतरपुर म.प्र.

छतरपुर दिनांक 26/10/22

पृ.क्र./वन अधिकार/2022-23/10688

प्रतिलिपि :-

1- वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल छतरपुर म०प्र० की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2- खनिज अधिकारी जिला छतरपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला संयोजक

जनजातीय कार्य विभाग

छतरपुर म.प्र.



कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी (सा.) वनपरिक्षेत्र बड़ामलहरा

एन.एच. 88 छतरपुर सागर रोड़ बड़ामलहरा

E - mail Id - RObadamalehra7@gmail.com mo no. - 9424791094

कमांक / मा0चि0व / 2023 / 619

बड़ामलहरा, दिनांक 11/04/2023

प्रति

श्रीमान् वनमण्डलाधिकारी महोदय
सा0 वनमण्डल छतरपुर (म0प्र0)

विषय:- छतरपुर जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 43 एक्सटेंशन गुलगंज- अमानगंज पवई-कटनी मार्ग के चौड़ीकरण/निर्माण हेतु 30.426 हेक्टेयर वनभूमि म0प्र0 सडक विकास निगम सागर को उपयोग पर देने बावत्।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क./मा.चि./2023/727 दिनांक 06.02.2023

—00—

महोदय

विषयांकित में निवेदन है कि सन्दर्भित पत्र से छतरपुर जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 43 एक्सटेंशन गुलगंज- अमानगंज पवई-कटनी मार्ग के चौड़ीकरण/निर्माण हेतु 30.426 हेक्टेयर वनभूमि म0प्र0 सडक विकास निगम सागर को उपयोग पर देने के संबंध में परिक्षेत्र सहायक गुलगंज से जांच कराई गई, बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

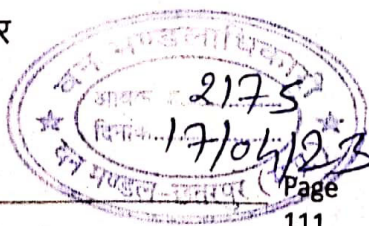
1. आवेदित क्षेत्र वनखण्ड गुलगंज अ के अंतर्गत आता है एवं मौके पर मिश्रित प्रजाति का आरक्षित वन है तथा 0.3 का घनत्व पाया गया।
2. मौका स्थल की प्रारम्भिक बिन्दु N 24° 40' 52.25" E 79° 21' 51.05" मध्य बिन्दु N 24° 40' 52.93" E 79° 21' 57.25" अंतिम बिन्दु N 24° 40' 54.05" E 79° 22' 02.42" जी.पी.एस. रीडिंग पाई गई।
3. मौके पर सतकठा एवं सागौन प्रजाति कुल 237 वृक्ष पाये गये।
4. मौके पर पहाड़ी क्षेत्र है।
5. क्षेत्र पर दुर्लभ प्रजाति, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल एवं कोई धार्मिक स्थल नहीं है।
6. क्षेत्र पर किसी भी वन्यप्राणी का रहवास स्थल नहीं पाया गया।
7. पर्यावरण भू-संरक्षण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
8. मौका स्थल से पन्ना टाइगर रिजर्व लगभग 80 कि.मी. दूरी पर है।
9. मौका स्थल पर कोई वनमार्ग रास्ता नहीं है।

प्रतिवेदन श्रीमान् की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मा0 चि0

0-5-0-Chhatarpur
13/4/23



Page
111

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र बड़ामलहरा

स्वपरेन गुलागंज वनपरिक्षेत्र वडागलहरा
दिनांक 20/3/23
७/७।

प्रति,

वनपरिक्षेत्राधिकारी महोदय
वनपरिक्षेत्र- वडागलहरा

विषय:- हतरपुर जिले में उद्घाटित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43
एक्सेलेशन गुलागंज- अमानगंज- पर्वत- कानी- मार्ग के चौड़ीकरण
निर्माण हेतु 30.4.26 हेम्ट. वनभूमि मध्य यड्ड विनास
निगम सागर को उपयोग पर देने वापस।

सन्दर्भ:- भीमान का पत्र क्रमांक / स्टेनो / 2023 / 456 वडागलहरा / दिनांक 21/3/23

जांच प्रतिवेदन

भीमान के सन्दर्भित पत्रानुसार मौका पर जांच डल कर
मौका स्थिति राष्ट्रीय राजमार्ग क्र 43 एक्सेलेशन गुलागंज-अमानगंज-
पर्वत- कानी मार्ग के चौड़ीकरण निर्माण हेतु 30.4.26 हेम्ट. वनभूमि मध्य
यड्ड विनास निगम सागर का उपयोग पर देने के लक्ष्य में जांच की गई
जिसमें उल्लेखित विनुक्तों की निम्नानुसार जांच की गई।

- ① आर्षेक्षेत्र वनखंड गुलागंज 'अ' के अन्तर्गत कागहें एवं मौके पर
मिलित जगति का आरक्षित वन है एवं 3 का घनत्व थापाया।
- ② मौका स्थल की आरक्षित विन्दु $N 24^{\circ} 40' 52.25''$ मध्यविन्दु $N 24^{\circ} 46' 52.93''$
 $E 79^{\circ} 21' 51.05''$ $E 79^{\circ} 21' 57.25''$
अंतिम विन्दु $N 24^{\circ} 46' 54.05''$ अप्स रीडिंग पाई गई।
 $E 79^{\circ} 22' 02.42''$
- ③ मौके पर सलख एवं सागौन जगति कुल 237 एकड़ पाई गई।
- ④ मौके पर पहाड़ी क्षेत्र है।
- ⑤ क्षेत्र पर दुर्लभ जगति महत्वपूर्ण लेसियॉडिड्स एवं कोई धार्मिक स्थल नहीं है।
- ⑥ क्षेत्र पर किसी भी वन्यजन्तु का दखलावा स्थल नहीं पाया गया।
- ⑦ मौका स्थल से पन्ना डाइगू रिवर लगभग 80 km दूरी पर है।
- ⑧ मौका स्थल पर कोई जनसंख्या रास्ता नहीं है।

उपर्युक्तानुसार विनुक्तों की जांच का प्रतिवेदन अधिसूचना के अनुसार
सादर सन्निहित है।

संलग्न:- ① मौका पचनागा

② गमना

③ पत्र क्र 456 दिनांक 12/3/23

परिक्षेत्र सहायक
गुलागंज

पंचनामा

इस आदेशानुसार जारी पंचनामा भूत पंचनामा लिखा देते हैं कि आदि 19/3/23 को श्री होरेलाल चौरिया परिवारे सहायक मुलाजिम एवं दल के सदस्यों सदस्य एवं लोक निर्माण विभाग के अभियंता के साथ श्रीमान वन परिदोषाधिकारी सहित बड़ा मालहरा के भूखंड 100/ रोजे 12023/456 दिनांक 12.03.2023 के परिणाम में आवेदन स्थल मुलाजिम अथवा मुलाजिम परी. करनी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 एक्सटेंशन के चौड़ीकरण हेतु मौका स्थापन किया गया जिसमें मौका स्थल आरम्भिक, मध्य एवं अंतिम बिन्दुओं की काप रीडिंग लेकर वीरमेप पर अंकित करने पर मौका स्थल क्रमांक R-71 क्रमांक 100/ मुलाजिम 100/ कीट मुलाजिम के अन्तर्गत वामागम्य मौका स्थल पहाड़ी क्षेत्र है। एवं मौके पर मिश्रित जंगल का आरक्षित वन है एवं मौका स्थल पर कोई धार्मिक देव स्थल नहीं पाया गया तथा मौका स्थल पर वृक्षों की गठना कराने पर कुल लागत एवं अलग से 237 रुपा पाये गये, जिसकी सूची के बाद भी गई, तथा मौका स्थल का 3 घनवर्ग है अथवा वन क्षेत्र से पूर्व निर्मित सड़क की कुल लम्बाई 50 मीटर गई एवं अन्तर्गत सड़क वन भूमि अन्तर्गत कुल लम्बाई 400 मीटर चौड़ाई 50 मीटर गई। मौका पंचनामा लिखा दिया गया कि सन्दर्भ रहे पत्र पर काम भावे।

काप रीडिंग

- ① आरम्भिक बिन्दु $N 24^{\circ} 40' 52.25''$
 $E 079^{\circ} 21' 51.05''$
- ② मध्य बिन्दु $N 24^{\circ} 40' 52.93''$
 $E 079^{\circ} 21' 57.25''$
- ③ अंतिम बिन्दु $N 24^{\circ} 40' 54.05''$
 $E 079^{\circ} 22' 02.42''$

पंचनामा भूखंडा पर लेखकिया गया।

हस्ताक्षर
अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार
ब.स. मुलाजिम

रामनाथ अबरवी

अभिषेक कुमार
ब.स. मुलाजिम

अभिषेक कुमार
ब.स. मुलाजिम

अभिषेक कुमार
ब.स. मुलाजिम

Purwa

Jhadwan

राष्ट्रीय राजमार्ग अंशक ५३

बेटल गार्डन
वीर-पुष्पांग कक्ष RTH- बनभरुस पुलिस थाना

Police chokki

मध्य बिन्दु (GAS)
N 24° 40' 52.93"
E 79° 21' 57.25"

अग्रिम बिन्दु
N 24° 40' 54.05"
E 79° 22' 02.42"

रत्नपुरा
पुनर्स्थापना पातन

Majhpara Pahar

पारमिन्त्र बिन्दु (GAS)
N 24° 40' 52.25"
E 79° 21' 51.05"

परिक्षेत्र सहायक
गुलामज

आम-1
1:50000
श्रीलंका स्थिति

Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Raod, Aliganj
New Delhi - 110003
Dated: the 6th July, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Minutes of the meeting held under the Chairmanship of the DGF&SS with MoRTH and NHAI Officials through VC on 24.06.2020 at 4:00 PM- reg

The undersigned is directed to enclose a copy of the minutes of the meeting on above mentioned subject held on 24th June, 2020 at 1600 hours through videoconferencing under the Chairmanship of Director General of Forests & Special Secretary, Ministry of Environment Forest and Climate Change for information and necessary action.

Encl. As above.

Sd/-
(Sandeep Sharma)
Asst. Inspector General of Forest
E-mail: ss.moef@gmail.com
Tel: 011-24695406

Distribution :

1. Shri I.K. Pandey, DG(Road Development) Special Secretary, MoRTH.
2. Dr. B Muhkopadhaya, General Manager, Environment Div., NHAI
3. IGF(WL)/IGF(FC)/IG(NTCA).
4. DIGF (ROHQ), MoEF&CC, New Delhi
4. Shri Satish Chandra Garkoti, Scientist-G, ESZ Division, MoEF&CC, New Delhi

Copy to:

1. PPS to Secretary MoEF&CC
2. PPS to DGF&SS, MoEF&CC.
3. PPS to Chairman NHAI.

Minutes of the meeting held under the Chairmanship of the DGF&SS with MoRTH and NHAI Officials through VC on 24.06.2020 at 4:00 PM

The following participants were present in the meeting:

Officials from MoEF&CC

1. Dr. Sanjay Kumar, DGF&SS, MoEF&CC
2. Soumitra Dasgupta, IGF (WL).
3. Anjan Kumar Mohanty, IGF (FC)
4. Dr. Amit Mallick, IGF (NTCA)
5. Shrawan Kumar Verma, DIGF (ROHQ)
6. Shri Satish Chandra Garkoti, Scientist-G
7. Sandeep Sharma, AIGF (FC)
8. Charan Jeet Singh, Scientist 'C' (FC)

Official from MoRTH

1. I.K. Pandey, DG(Road Development) Special Secretary, MoRTH.

Official from NHAI

2. Dr. B Muhkopadhaya, General Manager, Environment Div., MoRTH

The meeting was conducted through VC. Objective of holding the meeting was to initiate action/resolve certain issues taken up by the Group of Infrastructure in their meeting held on 25.02.3030. discuss

During the meeting following were discussed:

S. No. As per Agenda	Issue related to FC Division	Latest Decision/Status
(iii)	<p>Allotment of equivalent Revenue land in lieu of diversion of forest land for NH Projects executed by the State Governments/State Governments agencies:</p> <p>The issue was considered by the Forest Advisory Committee (FAC) in its meeting on 28.05.2020 and FAC after detailed deliberations desired that representatives from NHAI may be invited for further deliberation in the matter and the matter may again be placed</p>	<p>During the meeting, it was agreed by DG (Roads) that MoRTH will be entered as a "user agency" in the online application in PARIVESH, in such cases where work that is of Central Sector Project and is owned, developed and maintained by Central Government but the execution is carried out by a state government agency. As the user agency is MoRTH (Central Government) or a Central PSU, the dispensation of Compensatory Afforestation over double the degraded forest</p>

	before the Committee. In this regard A meeting was held between DGFSS (MoEFCC) and DG (Roads), MoRTH, where IG (FC) and officials of NHAI were also present.	land, instead of equivalent non-forest land will be available in such cases.
Issues related to Wildlife Division		
(vi)	Alignment of proposed Delhi-Mumbai Expressway in district Ratlam in M.P.	The draft E&Z notification for Sallana Wildlife Sanctuary has been re-issued on 20.03.2020. The proposal was considered in the meeting of the Expert Committee on E&Z held on 24 June, 2020. Further action will be taken by the E&Z Division.
(vii)	Wildlife clearance for the 4-laning project of NH-363 from Mancherla to Repallewada in Andhra Pradesh	The Government of Telangana has furnished SBWL recommendations and Animal Passage Plan through email on 22.06.2020. The proposal shall be placed before the SCNBWL during the next meeting to be held on 03.07.2020.
(viii)	6-laning of Vadakancherry - Thrissur on NH-544 in the State of Kerala	Addl. Chief Secretary, Deptt. of Forest, Kerala was reminded vide letter no. 6-183/2014 WL (Part 6) dated 15.05.2020. The matter was also pursued over phone with CWLW, Kerala. A D.O. letter from Secretary, EP&CC to Chief Secretary, Kerala was sent on 23.06.2020 regarding the matter. All the required documents have been received from the Government of Kerala and the proposal shall be placed for the consideration of SCNBWL during the next meeting to be held on 03.07.2020.
(ix)	4-laning of Haridwar - Nagina Section of NH-74	A committee was constituted by the Ministry on 18.05.2020 which included the DIG (WL), representatives from WI and NHAI and CWLW, Uttarakhand. Three meetings

		were convened and the committee submitted a consensus report on 22.06.2020. The Director, WII has agreed to the recommendations of the committee and the report submitted by the committee has been communicated to the Chairman, NHAI and CWLW, Uttarakhand for further action on 25.06.2020.
Issues related to ESZ Division:		
(iv)	<p>Withdrawal of MoEF&CC Notification regarding declaration of Eco-sensitive Zone in Uttarkashi District, Uttarakhand:</p> <p>Govt. of Uttarakhand proposed to MoEF&CC around 40 sq km of land in Uttarkashi on both side of Bhagirathi river - 100 meter from Gaumukh till Uttarkashi, 135 km long area as Eco Sensitive Zone (ECZ). MoEF&CC through notification dated 18.12.2012 declared 100 times more area around Bhagirathi as ECZ. GoU wants this notification withdrawn. The above notification will stall all projects of Indo-Tibet Border Road, CHAR DHAM Pariyojana and Namami Gange Pariyojana. Crores of devotees who will visit Kumbh Mela in 2021 in UT state will face hardships so immediate decision is to be taken.</p>	<p>The relevant notification has been amended in consultation with MoRTH on 16th April 2018 addressing the concerns, <i>inter alia</i> permitting change of landuse to meet the local needs including civic amenities and other infrastructure development in larger public interest and national security, protection of hill slopes, etc.</p> <p>Ministry of Jal Shakti has forwarded their comments on Zonal Master Plan in March 2020.</p> <p>The proposal has been considered in the meeting of the Expert Committee on ESZ held on 24 th June 2020 for approval of the ZMP. The proposal has been recommended for approval subject to certain information from the State Government for incorporation in the ZMP.</p>
(v)	<p>4-laning work from Tamil Nadu/Kerala Border to Kanyakumari in 2 packages</p> <p>The Hon'ble High Court of Madras has stopped the quarrying operations from the Eco Sensitive Zone up to 10 kms</p>	<p>The draft ESZ notification for Kanyakumari Wildlife Sanctuary has been re-issued on 21 st February, 2020.</p> <p>The proposal has been recommended for approval in the meeting of the Expert Committee on ESZ held on 24th June,</p>

	<p>boundary from the Kanyakumari Wildlife Sanctuary. As a result the projects are stalled as NHAI is unable to procure the raw materials (earth and aggregates) up to 10 kms boundary of the protected area.</p> <p>Govt. of Tamil Nadu has forwarded a proposal to MoEF&CC on 10.01.2020 along with the minutes of public hearing as desired by Expert Committee of ESZ to reduce the extent of boundaries of Eco Sensitive Zone from 0 to 3 kms. It was requested that the proposal of Govt. of Tamil Nadu may be considered at the earliest so that availability of borrow material is ensured for NHAI projects.</p>	2020,
(vi)	<p>Alignment of proposed Delhi-Mumbai Expressway in district Ratlam in M.P</p> <p>Alignment of proposed Delhi-Mumbai Expressway in district Ratlam in M.P. passes in the vicinity of Salaina Wildlife Sanctuary. As per the guidelines the project passes through Eco-sensitive zone (ESZ) within a radius of 10km, as there is no specific declaration of ESZ.</p> <p>The State Government has sent a proposal for notifying ESZ as 2km on 11.2.2020. It was requested that MoEF&CC may consider the proposal of Govt. of Madhya Pradesh for notifying the ESZ of 2km.</p>	<p>The draft ESZ notification for Sailana Wildlife Sanctuary has been re-issued on 20th March, 2020.</p> <p>The proposal has been recommended for approval in the meeting of the Expert Committee on ESZ held on 24th June, 2020.</p>

No. H-11013/02/2019-S&R(P&B)
Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
(S&R (P&B) Section)
Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi-110001

Dated: 30th June, 2020

To,

1. The Chief Secretaries of all State Governments/Union Territories
2. The Principal Secretaries/Secretaries of all States/U.Ts, Public Works Department dealing with National Highways, other Centrally Sponsored Schemes and State Schemes
3. The Engineers-in-Chief and Chief Engineers of Public Works Departments of States/U.Ts dealing with National Highways, other Centrally Sponsored Schemes and State Schemes
4. The Chairman, National Highways Authority of India(NHAI), G-5&6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075
5. Director, General (Border Roads,) Seema Sadak Bhawan, Ring Road, New Delhi-110010.
6. All Regional Officers, MoRTH

Subject:- Diversion of Forest Land for Development of National Highways Project.

Sir,

The Ministry of Road Transport and Highways is primarily responsible for the development and maintenance of National highways in the country through various agencies like State PWDs, NHAI, NHAIDCL, BRO etc. The development of National Highways may also involve diversion of forest land in certain locations/stretches.

2. It has come to the notice of the Ministry that for diversion of forest land, non-forest land is insisted in some of the States by the Forest Authorities especially for the National Highway Project being developed through State PWDs. A special dispensation has been given for the Central Government Project in departure from the general norms wherein afforestation in degraded forest land is allowed in lieu of the non-forest land.
3. This matter was further discussed in the meeting held between DG (F&SS), MOEFCC and DG(Roads)&SS, MoRTH. During the meeting, it was agreed by the DG(Roads) & SS that MoRTH will be entered as the "User Agency" in the online application in PARIVESH for the diversion of forest land required for National Highway Project, which are developed and maintained by the Central Govt. but the execution is carried out by State Agency. As such, the dispensation of the compensatory afforestation over double the degraded forest land, instead of equivalent non-forest land will be available in such cases.
4. In view of the above, all the State Agencies etc. are requested to do necessary compliance for the National Highway Development Project so that the unnecessary delay in identification for transfer of non-forest land could be avoided and approval of diversion of forest land could be expedited.

Yours faithfully,

(Chhaya

Rajput)

Signature Not Verified
Digitally signed by 21111A7A
RAJPUT
Date: 2020.07.04 12:24:50 IST

Assistant Executive Engineer (S&R) (P&B)

For Director General (Road Development) & SS

Copy to:

1. The Secretary General, Indian Roads Congress
2. Technical circular file of S&R (R) Section
3. NIC-for uploading on Ministry's website under "What's new"

Copy for kind information to:

1. Sr. PPS to Secretary (RT&H)
2. PPS to DG (RD) & SS
3. PPS to AS&FA
4. PS to ADG-I
5. PS to JS (T)/ JS (H)/ JS (LA&C)/ JS (EIC)